संख्या-12/1-ई.एम./2013-का-4-2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2013

विषय:-कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से की जा रही हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश में यह अपेक्षा की गयी थी कि ऐसे कर्मी, जो हड़ताल में शामिल हैं, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। साथ ही इनके विरूद्ध यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनता हो, तो ऐसे कर्मियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में किसी भी जनपद या विभाग से अभी तक कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

2. अग्रेतर आपको यह भी अवगत कराया जा रहा है कि कार्मिक अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3-ई.एम./2012-का-4-2013 दिनांक 19.11.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1996 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदेश के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा में तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में तथा किसी स्थानीय प्राधिकरी के अधीन सेवा में हड़ताल 19 नवम्बर, 2013 से 06 माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दी गयी है। इस संबंध में अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

3. उक्त अधिनियम की धारा-3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 निम्नानुसार हैं:-

3. Power to prohibit strikes in certain employment- If the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do, it may, by general or special order, prohibit strikes in any essential service specified in the order.

(2) An order made under sub-section (1) Shall be published in such manner as the State Government considers best calculated to bring it to the notice of the persons affected by the order.

(3) An order made under sub-section (1) Shall be in operation for six months only, but the State Government may by a like order, extend it for any period not exceeding six months if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do.

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) During the period of operation of an order under sub-section (1), any strike by persons employed in any essential service to which the order relates shall, whether it is declared or commenced before or after the commencement of the order, be illegal.

Which is illegal under this Act or goes or remains on, or otherwise takes part in any, such strike shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(5) Penalty for instigation, etc.- Any person who institates or incites other person to take part in. or otherwise acts in furtherance of, a strike which is or would be illegal under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with hoth.

(6) Penalty for giving financial aid to illegal strikes.- Any person who knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of a strike which is or would be illegal under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(7) Power to arrest without warrant.- Any police officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed any offence punishable under this Act.

(8) Act to over-ride other State Laws.- The provisions of this Act and of any order issued thereunder shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith contained in any other Uttar Pradesh Act for the time being in force.

अतएव आपसे अपेक्षा है कि लोक सेवाओं में हड़ताल में शामिल कर्मियों के विरूद्ध उक्त वर्णित अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा की गयी कार्यवाही से कार्मिक विभाग को अवगत कराया जाये।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1-ई.एम./2013(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in